

**EXTRAORDINARY** 

भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (ii) PART II--Section 3--Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 651] No. 651] नई दिल्ली, बृहस्पितवार, अक्तूबर 28, 1999/कार्तिक 6, 1921

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 28, 1999/KARTIKA 6, 1921

## गृह मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 1999

कां आ 1056 (अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार यह निर्धारित करने के लिए क्या आल त्रिपुरा टाइगर फोर्स और नेशनल लिब्रेशन फ्रंट आफ इंडिया को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं, एतद्द्वारा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री आर. आर. के. त्रिवेदी की अध्यक्षता में एक ''विधिविरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिकरण'' का गठन करती है।

[फा. सं. 9/14/99-एन.ई.-I] जी. के. पिल्ले, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 1999

S. O. 1056 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (I) of section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes "The Unlawful Activities (Prevention) Tribunal" consisting of Shri Justice R. R. K. Trivedi, Judge of Allahabad High Court, for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the All Tripura, Tiger Force and National Liberation Front of Tripura, as unlawful associations.

[F. No. 9/14/99-NE.-I] G. K. PILLAI, Jt. Secy.